

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,
लेखा एवं हकदारी,
सहारनपुर रोड़, माजरा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 17 फरवरी, 2017

विषय:— सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट देहरादून में अतिरिक्त निर्माण कार्यो हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी धनराशि के समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1147/बजट पत्रा/2016-17, दिनांक 10 जनवरी, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट देहरादून में अतिरिक्त निर्माण कार्यो हेतु सुसंगत मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण एवं कार्य की अपरिहार्यता तथा धन की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि **₹ 100.31 लाख (₹ एक करोड़ इक्तीस हजार मात्र)** की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से सुसंगत मद में **₹ 100.31 लाख** की बजट व्यवस्था से ही **₹ 100.31 लाख** की धनराशि के समायोजन की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3— इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 द्वारा सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट देहरादून में अतिरिक्त निर्माण कार्यो हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से **₹ 100.31 लाख** की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की गयी थी कि प्रश्नगत धनराशि की प्रतिपूर्ति/समायोजन वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

- 4- धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0-08 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।
- 6- धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- 7- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखा शीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-2001-समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-00-06-सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-310(P)/XXVII(3)/2016-17, दिनांक 10 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या- 38 /VI/2017-4(5)/2004 ,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय/वित्तीय डाटा सेन्टर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 7- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।